उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका (एम/एस) संख्या–661/2007

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम.....**याचिकाकर्ता**

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून एवं अन्य।.....**.प्रत्यर्थी**

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री राजीव सिंह बिष्ट।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री एम0 सी0 पन्त।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे(मौखिक)

वर्तमान रिट याचिका के याचिकाकर्ता ''यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम'' है, जैसा कि तब अस्तित्व में था, जो कानून का निर्माण है और यह एक वैधानिक निकाय है, और इसलिये निर्विवाद है, यह ''उद्योग'' की परिभाषा के अन्तर्गत आएगा, क्योंकि इसे ''यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(इसक बाद इसे ''यूपीआईडी अधिनियम'' के रूप में संदर्भित किया जायेगा) के तहत परिभाषित किया गया है। एक अन्य तथ्य, जिसे विशेष रूप से संदर्भ की आवश्यकता है कि प्रतिवादी नंबर 2/कर्मचारी, प्रासंगिक समय पर ''कंडक्टर'' के रूप में काम कर रहा था, जो याचिकाकर्ता के संगठन का कर्मचारी था और वहा एक मालिक और नौकर का रिश्ता मौजूद था, जो उनके बीच वास्तविक सम्बन्ध, जो आक्षेपित कार्यवाही होने तक कायम रहा है।

2. वर्तमान रिट याचिका के लिए याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी, जिसमें आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसे विद्वत श्रम न्यायालय, देहरादून द्वारा न्यायनिर्णयन मामले संख्या 134/2000 में दिनांक 12.02.2001 के एक पंचाट द्वारा प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, विद्वत श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या. 2/कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के आदेश को अपास्त करते हुए, जिसे दिनांक 26.11.1999 के आदेश द्वारा बनाया गया था, इसे अवैध और शून्य मानते हुए रद्द कर दिया था, सेवाओं के वितरण के आदेश के स्थान पर दंड आदेश को वार्षिक वृद्धि के ठहराव में परिवर्तित करके संशोधित करे। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.02.2001 के पंचाट के तहत सजा के संशोधित आदेश के तहत याचिकाकर्ता की सेवा में बहाल किया गया था।

3. रिट याचिका जो याचिकाकर्ता/नियोक्ता द्वारा 13.12.2001 को आरंभ की गई थी और विभिन्न खातों पर वाद संख्या 134/2000 के न्याय निर्णयन में दिए गए उपर्युक्त पंचाट को चुनौती देते हुए त्वरित रिट याचिका दायर की गई थी।

4. विवाद का इतिहास, जो वर्तमान रिट याचिका में विचार करता है, वह प्रतिवादी संख्या 2/कर्मचारी है, जो याचिकाकर्ता के संगठन के साथ कंडक्टर के रूप में काम कर रहा था। उस समय, जब उत्तरदाता no.2 अपनी सेवाओं को वितरित कर रहा था i.e. दिनांक 11.07.1995 को जिस बस को चलाया जा रहा था, देहरादून–कुलहन रोड पर, पंजीकरण संख्या यू0एम0एल0/9133, प्रतिवादी संख्या.2 उक्त बस का कंडक्टर था। उक्त तिथि पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व वाली टीम द्वारा उक्त बस का निरीक्षण किया गया और आकस्मिक निरीक्षण पर, जाँच प्राधिकरण ने पाया कि उक्त बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या में से लगभग 25 यात्री थे, जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे।

5. निरीक्षण के चरण में ही, चेकिंग प्राधिकरण ने उन यात्रियों को टिकट जारी किए थे, जिन्हें बिना टिकट के ले जाया जा रहा था और वे टिकट रहित यात्री पाए गए थे और टिकटों में उक्त प्रभाव का एक निशान भी था, जो उपरोक्त यात्रियों को जारी किए गए थे, साथ ही रूट चार्ट में इसका एक संदर्भ भी बनाया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि चेक टिकट जारी किए गए थे, निरीक्षण दल की चेकिंग टिप्पणियों के तहत, जो चेकिंग प्राधिकरण द्वारा 11.07.1995 को बस पर आयोजित किया गया था। इसके अलावा, जिस तथ्य का अनुरोध किया गया है, वह यह था कि जब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की अध्यक्षता वाली निरीक्षण टीम ने यात्रियों को टिकट जारी किए थे, तो वे बिल को भी प्रतिवादी संख्या 2,3 द्वारा सावधानीपूर्वक समर्थन दिया गया था ताकि इस तथ्य को मजबूत किया जा सके कि 25 यात्री बस में बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। अंततः सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की अध्यक्षता वाले जाँच प्राधिकरण ने 11.07.1995 को ही सक्षम प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

6. 18.07.1995 को, निरीक्षण दल द्वारा 11.07.1995 को प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट की सामग्री को मजबूत करने के लिए, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने प्रतिवादी संख्या 2/कर्मचारी को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन आरोपों के सेट और निष्कर्षों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था, जो उनके खिलाफ रिपोर्ट में दर्ज किए गए थे, जो दिनांक 11.07.1995 की जाँच प्राधिकरण की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। प्रतिवादी संख्या. 2 को दिये गये नोटिस देने पर कोई विवाद नहीं है और इसके

जवाब में, प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के समक्ष अपना जवाब भी प्रस्तुत किया था।

7. अनुशासनात्मक प्राधिकरण सेवा नियमों के अनुसार को "यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों के अलावा) सेवा नियम, 1981 (इसके बाद से "सेवा नियम, 1981" कहा जायेगा), अनुशासनात्मक प्राधिकरण कहा जाता है। कंडक्टर के मामले को क्षेत्रीय प्रबंधक माना गया है। अतः क्षेत्रीय प्रबंधक ने 06.09.1995 को जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या. 2 को एक पत्र जारी किया है, दिनांक 11.07.1995 की रिपोर्ट की सामग्री के आधार पर एक बार फिर प्रतिवाद/कम्रचारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। एक बार फिर यह एक तथ्य है जो रिकॉर्ड से सामने आया है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20–09–1995 के आदेश द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक और अंततः अनुशासनात्मक प्राधिकारी के उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया। कार्मिक को दिनांक 06.09.1995 को जारी किये गये नोटिस तथा दिनांक 11.07.1995 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप पत्र जारी किया था।

8. 20.09.1995 को प्रत्यर्थी संख्या. 2/कामगार को आरोपपत्र जारी किए जाने पर, क्षेत्रीय प्रबंधक ने सेवा नियमों के अनुसार कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये दिनांक 14.03.1996 को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया था क्योंकि यह प्रत्यर्थी संख्या. 2 की सेवा शर्तों पर तब लागू था और श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेजों और निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैंः–

(ए) 11.07.1995 की रिपोर्ट और दिनांक 20.09.1995 की आरोप पत्र, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा मांगे गए उत्तर के साथ प्रतिवादी संख्या 2 की प्राप्ति में थे।

(बी) इसमें कोई विवाद नहीं था कि प्रतिवादी संख्या. 2, प्रासंगिक तिथि 11.07.1995 को कंडक्टर के रूप में तैनात किया गया था, और उक्त क्षमता में काम कर रहा था जब उपरोक्त बस को मार्ग पर चलाया जा रहा था, तब वह उक्त क्षमता में काम कर रहा था। पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया था।

(सी) प्रत्यर्थी संख्या. 2 द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं है कि उसने नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया था, जो शुरू में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा 11.07.1995 को जारी किया गया था, और बाद में क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा, निरीक्षण प्राधिकरण की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.07.1995 के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्यों के लिए कारण बताओ नोटिस।

(डी) अभिलेख से जो निर्विवाद तथ्य स्पष्ट है वह यह है कि प्रत्यर्थी संख्या. 2, कर्मकार ने विभागीय कार्यवाहियों में प्रभावी रूप से भाग लिया था, जो उसके विरुद्ध की गई थी। उन्हें अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का भी अवसर दिया गया था।

(ई) इस पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने अभियोजन पक्ष के उन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की, जिन्होंने दिनांक 11–07–1995 की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 20.09.1995 के आरोपपत्र में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया था।

9. अंततः, जांच कार्यवाहियों के समापन पर, अपनी रिपोर्ट (अनुलग्नक संख्या. 6) में, जांच अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया है कि मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों के मूल्यांकन पर, कि प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वयं को गलत तरीके से पेश किया है और प्रत्यर्थी संख्या. 2,5 के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सेट एक कदाचार होगा, जैसा कि 1981 के नियमों के तहत परिभाषित और विचार किया गया है, जो गंभीर प्रकृति का है, और विशेष रूप से, आरोपों का सेट, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है और जिसे जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों में दर्ज और साबित किया गया था, सेवा नियमावली 1981 के नियम 1981 के नियम 61 के प्रावधानानुसार प्रत्यर्थी संख्या. 2 का आचरण आचरण/कदाचार के मापदंडों के भीतर होगा।

10. परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों से संतुष्ट होने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में, और जांच रिपोर्ट की सामग्री से सहमत होने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सेवा नियम, 1981 के भाग 10 के प्रावधानों के अनुसार 05.05.1997 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्षों के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो प्रतिवादी संख्या 2 के कथित कदाचार को स्थापित करता है, जो दिनांक 05.05.1997 के कारण बताओ के अनुसार 1981 के नियमों के नियम 61 के तहत आने वाला एक गंभीर कदाचार था। इस प्रकार जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति कारण बताओ 05.05.1997 को जारी किया गया।

11. प्रतिवादी संख्या. 2 ने कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति पर, जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण/दंडित करने वाले प्राधिकरण द्वारा 05.05.1997 को जारी किया गया था, जांच रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के साथ, जो जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था, दिनांक 19.05.1997 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण/दंडित करने वाले प्राधिकरण के दिनांक 05.05.1997 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, कर्मचारी/प्रतिवादी संख्या.2 पर प्रस्तावित जुर्माना लगाने की पूर्व शर्तों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए अनुरूप था।

12. प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने दिनांक 19.05.1997 को दिनांक 05.05.1997 को विस्तृत उत्तर संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया। नतीजतन, दंडित करने वाले प्राधिकरण/अनुशासनात्मक 6 प्राधिकरण/क्षेत्रीय प्रबंधक ने कामगार/प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सेट को स्थापित करने और साक्ष्य द्वारा गंभीर कदाचार साबित करने के बाद, दिनांक 26.11.1999 को एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत, प्रत्यर्थी संख्या 2 की सेवाओं को एक कर्मचारी/कंडक्टर के रूप में समाप्त कर दिया गया था। दिनांक 26.11.1999 का आदेश संख्या. 1214, कर्मकार को विधिवत रूप से दिया गया था।

13. नियोक्ता/याचिकाकर्ता के साथ एक कर्मचारी होने के नाते, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यूपीआईडी अधिनियम की धारा 4–के के तहत निहित प्रावधानों को लागू किया था, जिसमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए एक औद्योगिक विवाद का संदर्भ मांगा गया था। राज्य सरकार संदर्भ से संतुष्ट हो रही है क्योंकि यह सरकारी आदेश संख्या 5409–13/D. Dun–C.P. द्वारा किया गया था। 11/2000 दिनांक 02.08.2000; दिनांक 26.11.1999 को बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अदालत के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय को एक विवाद भेजा था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे संदर्भ पर, उपरोक्त न्यायनिर्णयन मामले को निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था और इसे **न्यायनिर्णयन मामले संख्या 134/2000** के रूप में दर्ज किया गया था और संदर्भ का निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया गया थाः–

> ''क्या सेवायोजक द्वारा अपने कर्मचारी श्री उदय चन्छ रमालेला पुत्र श्री मातवर सिंह परिचालककी सेवायें दिनांक 26–11–99 को समाप्त किया जाना अनुचित/अवैधानिक है यदि हॉ तो वादी श्रमिक क्या हितलाभ/अनुतोष पाने का अधिकारी है एवं अन्य किस विवरण के साथ।''

14. वाद संख्या 134/2000 के न्यायनिर्णयन 02.08.2000 को पंजीकरण की कार्यवाही पर नोटिस जारी करने पर, याचिकाकर्ता/नियोक्ता ने 14.12.2020 को अपना लिखित बयान दायर किया और इसने उन आरोपों का समर्थन किया है जिन्हें

आरोप पत्र और रिपोर्ट में संदर्भित किया गया था और निष्कर्ष जो जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए थे। कर्मचारी के लिखित बयान का एक जवाबी जवाब भी याचिकाकर्ता नियोक्ता द्वारा 03.02.2001 को अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

15. प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने भी अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया था, हालांकि उसने आरोपों को नकारने का प्रयास किया था जो लगाए गए थे और साबित हुए थे और नियोक्ता/याचिकाकर्ता के लिखित बयान में अपनी प्रतिकृति भी दायर की थी। अंततः, उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, विद्वान श्रम न्यायालय ने केवल इस आधार पर एक आक्षेपित पंचाट पारित किया था कि "इसे प्रतिवादी संख्या. 2 के खिलाफ लगाए गए आरोपों या कदाचार के अनुरूप नहीं माना गया था।

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, और विशेष रूप से याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उन निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया था, जो विद्वत श्रम न्यायालय द्वारा दो प्रमुख संभावनाओं से अभिलिखित किए गए हैंः–(i) यह कि कामगार/प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने श्रम न्यायालय के समक्ष अपने तर्क को केवल उस दंड के संबंध में सीमित कर दिया था जो अधिरोपित किया गया था। (ii) प्रत्यर्थी संख्या.2/कर्मचारी ने यूपीआईडी अधिनियम की धारा 11–ए के तहत निहित प्रावधानों के आधार पर सजा के असमान रूप से निर्धारण के एक पहलू में हस्तक्षेप करने के लिए श्रम न्यायालय की क्षमता पर मुद्दे को संबोधित किया है, जिसमें, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के तहत हस्तक्षेप का एक निश्चित अक्षांश जिसके तहत घरेलू जांच की गई थी, को श्रम न्यायालय द्वारा उद्यम करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। यू0पी0आई0डी0 की धारा 11–A का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे यहाँ उद्धृत किया गया हैः–

> "**11–क– शक्तियों का प्रत्यायोजन**–राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो निर्देश में, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।"

17. यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं हो सकता है कि मामले के तथ्यों के तहत श्रम न्यायालय भी अपनी सीमा के तथ्य से अवगत था, जबकि यू. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 11–ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असमान रूप से दंड से संबंधित था, यू. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 11–ए के तहत हस्तक्षेप के

दायरे का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब श्रमिकों पर लगाए गए दंड ने स्वयं श्रम न्यायालय की चेतना को हिला दिया हो, जिसे अन्यथा अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि लगाया गया दंड असमान था। श्रम न्यायालय ने निरीक्षण प्राधिकरण, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और उन परिस्थितियों की पुनः समीक्षा करके समाप्ति के आदेश में दिए गए कारणों की भी जांच की है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 को बस में 11.07.1995 को बिना टिकट के 25 यात्रियों को ले जाते हुए पाया गया था, बल्कि श्रम न्यायालय, देहरादून ने कहा है कि हालांकि उक्त कदाचार संभव था, लेकिन जब से निरीक्षण स्वयं 08:00 बजे किया गया था और लगभग 100 यात्री थे, जो उस समय बस में यात्रा कर रहे थे, श्रम न्यायालय ने कहा है कि सभी संभावनाओं में प्रतिवादी संख्या 2 के लिए टिकट जारी करने के लिए परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हो सकती हैं और इसलिये इस पर विचार किया गया है। श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 26–11–1999 को पारित निरस्तीकरण के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया।

> ''अतः मैं अभिनिर्णय देता हूं कि सेवायोजकों द्वारा अपने कर्मचारी उदयचन्द रमोला पुत्र श्री मातवर सिंह, परिचालक की सेवायें दिनांक 26–11–99 से समाप्त किया जाना अनुचित व अवैधानिक है और इसके स्थान पर उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया जाता है जिसका भविष्यगामी प्रभाव नहीं होगा। वादी श्रमिक की सेवा में पुर्नस्थापित किया जाये तथा पिछली अवधि का पूर्ण वेतन व रू0 1,000/– वाद व्यय दिया जाये।''

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि दुराचार की गंभीरता को निर्धारित करने के लिए पैरामीटर जो एक कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए थे, हमेशा परिप्रेक्ष्य और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिसके तहत कदाचार कर्मकार/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया था, इसके मूल्यांकन के लिए एक सामान्य मापदंड नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि कदाचार की व्याख्या, विशेष रूप से, वैधानिक परिवहन निगम के संबंध में, एक बार जब यह एक गंभीर कदाचार से संबंधित है, जहां उसके कर्मचारी द्वारा मास्टर के बीच विश्वासघात होता है और वित्तीय गबन के प्रभाव के परिणामस्वरूप टिकट जारी न करने में स्पष्ट लापरवाही होती है, तो उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट जारी न करना या बिना टिकट के यात्रियों को ले जाना, अपने आप में एक गंभीर कदाचार होगा और इसमें एक कर्मचारी की सेवा का वितरण शामिल होगा और जब किसी कर्मचारी के वित्तीय अनियमितता के आचरण में संलग्न होने के कारण उसके कर्मचारी पर नियोक्ता का विश्वास कम हो जाता है, तो उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि श्रम न्यायालय का निर्णय, कानून की नजर में बुरा होगा; इसका कारण यह है कि यूपीआईडी अधिनियम की धारा 11–ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सजा के

आदेश में संशोधन, उचित रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है, और लगाए गए आरोपों को फिर से सराहना की जा सके। यह स्थापित किया गया है कि प्रतिवद्ध किया गया था और केवल वह पहलू जो श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया था, वह सजा के अनुपात के संबंध में था और उसके तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम प्रदीप कुमार में 2016 (15) (एससीसी) 122** में, विशेष रूप से, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 4, 5 और 6 की ओर आकर्षित किया है और संदर्भित किया गया है–

> "4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। उसने प्रस्तुत किया कि श्रम अदालत द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था क्योंकि कथित कदाचार गंभीर प्रकृति का था। कर्मचारी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था वह यह है कि उसने 78 यात्रियों से किराया लिया था और उन्हें टिकट जारी नहीं किया था, जो विश्वास का आपराधिक उल्लंघन है। एक बार इस तरह का कदाचार साबित हो जाने के बाद, कामगार को बहाल करना उचित नहीं हो सकता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि श्रम न्यायालय, एक उपयुक्त मामले में, दी गई सजा में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब ऐसी सजा अन्यथा उचित नहीं है। रिलायंस को U.P. के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। राज्य सड़क परिवहन निगम, देहरादून बनाम सुरेश पाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। सुसंगत पर्यवेक्षण निम्न है–
>
> > 7. वर्तमान मामले में हमारे विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संशोधित दंड न्यायसंगत है या नहीं? विद्वत एकल न्यायाधीश ने पाया कि वर्तमान मामले में दी गई सजा अपराधी के अपराध के अनुपात में नहीं है। जहाँ तक याचिकाकर्ता के अपराध का संबंध है, घरेलू जांच में यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता बीस यात्रियों को टिकट जारी नहीं करने का दोषी है और घरेलू जांच के इसी निष्कर्ष को श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। याचिकाकर्ता एक संचालक था और न्यास का पद धारण करता था। यदि याचिकाकर्ता जैसे पदधारी टिकट जारी नहीं करके और पैसे को जेब में डालकर पैसे का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं जिससे निगम को नुकसान होता है तो यह एक गंभीर कदाचार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को 1988 में नियुक्त किया गया था और सेवा के पहले वर्ष में वह कदाचार में लिप्त होने लगा तो भविष्य में उससे क्या उम्मीद की जा

सकती है। यदि सेवा के पहले वर्ष में यह स्थिति है और यदि ऐसे व्यक्तियों को हल्की सजा देने की अनुमति दी जाती है तो यह समान रूप से स्थित अन्य व्यक्तियों के लिए एक गलत संकेत होगा। इसलिए, ऐसे मामलों में पदधारी को जितनी जल्दी हो सके बाहर कर दिया जाना चाहिए और इसे श्रम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। हमारा दृढ़ मत है कि ऐसी घटनाओं से हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि निगम और अन्य सहकर्मियों में वातावरण प्रदूषित हो।

8. आम तौर पर, न्यायालय तब तक सजा को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं जब तक कि वे चौंकाने वाले अनुपातहीन नहीं होते हैं यदि सजा को उनके असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सजा में हस्तक्षेप किया जाता है या हल्के ढंग से प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यदि इस तरह के कदाचार से हल्के में निपटा जाता है और अदालतें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में कम सजा को प्रतिस्थापित करना शुरू कर देती हैं तो यह समाज में गलत संकेत देगा। देश के सभी राज्य सड़क परिवहन निगम इस तरह के अधिकारियों के कदाचार के कारण परेशान हो गए हैं, इसलिए यह समय है कि कदाचार से सख्ती से नहीं, बल्कि सख्ती से निपटा जाए।

9. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने यू.पी.एस.आर.टी.सी. में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। v. होटी लाल, जिसमें इस न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह कथन कि यह असंगत है, एक कम सजा के स्थान पर पर्याप्त नहीं होगा। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवधारित किया:

> सजा की मात्रा पर विचार करते समय न्यायालय या न्यायाधिकरण को यह कारण दर्ज करना होगा कि यह क्यों महसूस किया जाता है कि सजा सिद्ध आरोपों के अनुरूप नहीं थी। हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है और

असाधारण मामलों तक ही सीमित है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है कि सजा को अनुपातहीन क्यों माना गया था। कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है। **केवल यह कथन कि यह अनुपातहीन है, पर्याप्त नहीं होगा। यह न केवल शामिल राशि है, बल्कि मानसिक व्यवस्था, किए गए कर्तव्य का प्रकार और इसी तरह की प्रासंगिक परिस्थितियाँ हैं–सजा आनुपातनिक या असंगत, इस पर विचार करते हुए प्रकिया बनाना। यदि कारण नहीं बताया गया है कि सजा को आनुपातहीन क्यों माना गया।यदि प्रभारित कर्मचारी विश्वास का पद धारण करता है जहां ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कार्य करने की अंतर्निहित आवश्यकताएं हैं, तो मामले से नरमी से निपटना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में कदाचार से सख्ती से निपटना पड़ता है।** जहाँ व्यक्ति सार्वजनिक धन के साथ सौदा करता है या वित्तीय लेनदेन में लगा हुआ है या एक जिम्मेदार क्षमता में कार्य करता है, वहाँ उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता आवश्यक और अप्रत्याशित है। उस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्ष उचित नहीं हैं।

इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी को देखते हुए इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है।

5. हम विशेष रूप से सुरेश पाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को अनुपालन में रखते हुए अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में योग्यता पाते हैं, जो स्पष्ट रूप से हाथ में मामले पर लागू होता है।

6. तदनुसार, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के साथ–साथ श्रम न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हैं और सजा के आदेश को बहाल करते हैं।

19. प्रदीप कुमार (सुप्रा) के मामलों में उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां किसी कर्मचारी या कर्मचारी द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन होता है, और विशेष रूप से, परिस्थितियों के सेट में, जो बिना

टिकट के यात्रियों को ले जाने की प्रकृति में लगभग समान था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां भी वित्तीय अनियमितता के कारण विश्वास का उल्लंघन होता है, वहां सेवा में बहाली का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यू. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 11–ए के तहत सजा को संशोधित करने का उक्त श्रम न्यायालय का निर्णय, उस दायरे और भावना से बाहर था, जिसके लिए यू. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 11–ए के तहत निहित प्रावधानों को विधायिका द्वारा शामिल किया गया था।

20– याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने एक और निर्णय का उल्लेख किया था जो U.P. राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम गोपाल शुक्ला और एक अन्य ने 2015 (8) एससीसी 241 में रिपोर्ट किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में भी लगभग यह मत व्यक्त किया है कि यू. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 6 (2–ए) की सहायता से संचयी प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धि को रोकने के लिए बर्खास्तगी के दंड का प्रतिस्थापन, जिसे अधिनियम की धारा 11–ए के साथ पढ़ा जाएगा; केवल वित्तीय अनियमितता में लगे कर्मचारी को दया के सिद्धांत के आधार पर नहीं दिया जा सकता था, और इसलिए 25 यात्रियों को बिना टिकट के ले जाने के आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के साथ बरकरार रखा गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपरोक्त परिस्थितियों और पृष्ठभूमि में श्रम न्यायालय द्वारा सजा में संशोधन का जोखित नहीं उठाया जाना चाहिए था। पैराग्राफ संख्या 12,13 और 14 की सामग्री के लिए संदर्भ दिया जा सकता है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि श्रम न्यायालय या उस मामले के लिए उच्च न्यायालय, जहां टिकट के बिना यात्रियों को ले जाने के आरोपों का सेट स्थापित किया गया है, कर्मचारी कंडक्टर के खिलाफ है। न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भ्रष्ट है, न्यायिक आश्रय देने की कार्यवाही में विलंब करना चाहिए और उस प्रयोजन के लिए उक्त निर्णय के पैरा संख्या 12,13 और 14 का भी निर्देश हो सकता है, जो दिए गए हैं:–

> "12. उक्त कारणों पर एक नज़र डालने पर, यह काफी स्पष्ट है कि कारण वास्तव में काल्पनिक हैं और श्रम न्यायालय द्वारा कुछ प्रकार की अस्वीकार्य सैद्धांतिक धारणाओं को प्रकट करते हैं। **संचालक का आचरण स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि व्यक्तिगत लाभ का तथ्य स्थापित किया गया था।** यह कारण कि यात्रियों ने शिकायत की होगी और उन्होंने कंडक्टर का पक्ष नहीं लिया होगा और कंडक्टर के खिलाफ शिकायत की होगी, किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं, बल्कि श्रम न्यायालय की जन्मजात रचनात्मकता द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है, कोई वसूली

नहीं हो सकती थी। राशि की वसूली न होने का मतलब यह नहीं है कि कंडक्टर को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ था या कर्मचारी द्वारा वेबिल के गलत स्थान के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करके व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रष्टाचार को छिपाया गया था। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त आरोप घरेलू जांच में साबित हुआ है। श्रम न्यायालय ने वास्तव में उस निष्कर्ष को खारिज नहीं किया है। यह वास्तव में अस्थिर तरीके से आगे बढ़ा है और गबन के मुद्दे पर आगे बढ़ा है। **यह इन तथ्यों से पूरी तरह से अनजान रहा है कि कंडक्टर ने 25 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दी थी; कि उक्त अधिनियम के कारण, निगम को नुकसान हुआ था; कि उसने शरारत से पुलिस स्टेशन में अपने द्वारा वेबिल को गलत स्थान पर रखने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी; कि उसका आचरण स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए उसकी संलिप्तता को दर्शाता है, और कि अंतिम कार्य उस भ्रष्टाचार को छिपाना था जो उसके व्यक्तिगत लाभ में निहित था।** इस आधार पर श्रम न्यायालय 13 द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष बिल्कुल विकृत है और उच्च न्यायालय ने कारणों को दोहराया है और निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होना चाहिए कि व्यक्तिगत लाभ से संबंधित आरोप साबित हो गया है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसके विपरीत निष्कर्ष स्पष्ट को नजरअंदाज करने और एक तरह से पिंचबेक को वास्तविक मानने के समान होगा। हालांकि तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष है, लेकिन दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत है, इसे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यह अलामेलु बनाम राज्य (2011) 2 एससीसी 385), हेंज इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम U.P. राज्य में प्रावधानित किया गया है। (2012) 5 एससीसी 443) और विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल (2012) 7 एससीसी 288) में प्रावधानित किया गया है।

13. उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही प्रत्यर्थी–कामगार पर कम दंड अधिरोपित करके गलती की हैं, जबकि एकमात्र दंड, उन आरोपों की स्थापना पर जो श्रम न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए हैं, बर्खास्तगी होनी चाहिए थी न कि कम

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, **हमें यह कहने के लिए प्रेरित किया जाता है कि श्रम न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 6**

(2–ए) के तहत शक्ति का प्रयोग बिल्कुल मनमाना है और यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि इसका प्रयोग न्यायिक तरीके से नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जब हमने आगे कहा है कि व्यक्तिगत लाभ से संबंधित आरोप स्थापित किया गया है, तो उक्त दृष्टिकोण को अधिक समर्थन मिलता है। जैसा कि शोभा सुरेश जुमानी बनाम अपीलीय अधिकरण, (2001) 5 एस. सी. सी. 755 में देखा गया है कि भ्रष्टाचार में कैंसर की वृद्धि हुई है जिसने लोगों के नैतिक मानकों और सरकारी प्रशासन के सभी रूपों को प्रभावित किया है।

21. **निरंजन हेमचन्द्र सशित्तल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 4 (एससीसी), 642** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत भी वित्तीय लाभ में लगे भ्रष्ट कर्मचारी से निपटने के लिए एक समान मापदंडों को निर्धारित करता है, उन्हें कोई सांत्वना नहीं दी जानी चाहिए।

22. इसके विपरीत, यूपीआईडी अधिनियम की धारा 11–ए के निहितार्थ को निकालकर प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील का तर्क, जिसे यहां उद्धृत किया गया है:–

> "11–ए। शक्तियों का प्रत्यायोजन– राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, निर्देश में, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

23. प्रत्यर्थी संख्या. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा था कि दंड को संशोधित करके आक्षेपित पुरस्कार पारित करके शक्तियों का प्रयोग पूरी तरह से उचित था और इसलिए, इस न्यायालय को; श्रम न्यायालय द्वारा यूपीआईडी अधिनियम की धारा 11–ए के दायरे में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद मामले के संभावित पहलू में प्रवेश नहीं करना चाहिए और उसके संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने **एफएलआर 2000 (85) पृष्ठ 284"यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुभाष शर्मा और अन्य"** के साथ–साथ **2015 (एससीसी) 12, पृष्ठ 408,"एच. एल. गुलाटिव्स बनाम भारत संघ और अन्य"** और अंत में उन्होंने में रिपोर्ट किए गए "**संतराम वी. राजिंदरलाल ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1601"** के मामले में दिए गए निर्णय को संदर्भित किया है।

24. जहां तक प्रत्यर्थी संख्या. 2/कर्मचारी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क यह है कि उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, लगाए जाने वाले दंड को कम करने के प्रयोजनों के लिए, मैं उस तर्क से असहमत हूं जो प्रत्यर्थी संख्या. 2/कर्मचारी के लिए विद्वान वकील द्वारा बढ़ाया गया है, और सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करने का तर्क है, जैसा कि दबाया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी संख्या. 2 के लिए विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामले, अधिकारी थे जो हालांकि टिकट के बिना यात्रियों को ले जाने के एक पहलू को संलग्न कर रहे थे, लेकिन यह एक मुद्दा शामिल नहीं कर रहा था कि क्या टिकट के बिना 25 यात्रियों में से 15 को ले जाने का तथ्य एक स्वीकृत तथ्य था।

25. उन कारणों के लिए जो तथ्यात्मक निर्धारण की प्रक्रिया में दर्ज किए गए हैं, जो ऊपर दिए गए हैं, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या. 2 ने बिना टिकट के 25 यात्रियों को ले जाने के कार्य को स्वीकार किया था और मेरी राय के अनुसार एक बार एक वित्तीय जिम्मेदारी एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को सौंपी जा रही है, और विशेष रूप से, राज्य परिवहन निगम के कंडक्टर के लिए, यह एक नियोक्ता का ट्रस्ट है, जिसका उल्लंघन किया गया है, यदि वह बिना टिकट के यात्रियों को ले जाता है और कोई सहानुभूति या उदार दृष्टिकोण या नरम दृष्टिकोण नहीं रखता है, तो सजा और इसकी परिमाण को कम करके लिया जा सकता है क्योंकि स्थापित आरोप स्वयं, जिनके वित्तीय निहितार्थ निपटान के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त थे।

यहां तक कि यदि यू. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 11–ए के वैधानिक अधिदेश के अनुसार निहितार्थ को ध्यान में रखा जाता है, जो एक सरकारी राजपत्र द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर शक्तियों के प्रयोग पर विचार करता है, तो भी सेवा नियम, 1981 के भाग 9 के कदाचार के उल्लंघन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

26. उपर्युक्त कारण के लिए, जांच कार्यवाही की जांच, जिसे कामगारों द्वारा विवादित नहीं किया गया था और यूपीआईडी अधिनियम की धारा 11–ए के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सजा को संशोधित करके, मेरा विचार है कि दी गई परिस्थितियों के तहत और विशेष रूप से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए फैसले को देखते हुए, श्रम न्यायालय ने भविष्य के प्रभाव से वार्षिक वृद्धि को रोकने के दंड में परिवर्तित करके सजा को संशोधित करने में हस्तक्षेप करने में कानूनी रूप से गलती की है, क्योंकि बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के आरोपों को देखते हुए, सेवा को बर्खास्त करके लगाये गये दण्ड की प्रकृति पर्याप्त चौंकेने वाली नहीं है।, जो अन्यथा सबूतों के आधार पर साबित हुआ था, जिसे रिकार्ड पर रखा गया था और प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ जांच कार्यवाही में बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया गया था। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी विवाद नहीं किया गया था, गंभीरता से

सवाल उठाते हुए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में कोई प्रकियात्मक दोष था।

27. परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। दिनांक 20.08.2001 का आक्षेपित अधिनिर्णय, जैसा कि 27.08.2001 को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया गया था, जिसे 134/2000 के न्यायनिर्णयन मामले में प्रस्तुत किया गया था, को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.1999 के सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया है।

28. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या. 2/कर्मकार, 29.06.2011 की दुखद मृत्यु हो गयी थी और उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया गया था; यह अभिनिर्धारित करते हुए कि बर्खास्तगी कदाचार के सेट के तहत उचित थी जो प्रत्यर्थी संख्या. 2 (मृत) के खिलाफ की गई थी। यदि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या. 2 (मृतक) के उत्तराधिकारियों को प्रश्नगत अधिनिर्णय के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय/और अन्य लाभ का भुगतान किया गया है, तो उन्हें वापस भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उक्त लाभ का लाभ उठाने में कानून की किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब इस न्यायालय ने वर्तमान निर्णय के आधार पर बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा है, तो विभाग द्वारा लागू नियमों के अनुसार कोई सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई देय हो, का भुगतान नहीं किया जाएगा।

29. उपरोक्त कारणों से रिट याचिका स्वीकार की जाती है, विवादित पंचाट को रद्द किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे।)